-SSS/NBR-PSV/1U/3.00

SHRI P. CHIDAMBARAM (CONTD.): People asked me, "When will it end?" I said, "If would not end. It will simply take a down and in over six to eight months, it will come back to normal. But, in the meanwhile, the economy would have been severely damaged."

Sir, let me conclude by saying, this Budget has been a great disappointment to me. But, the common man will not use these economic terms. He will say, and he is entitled to say and I said it also, it is a damp squib. It is as if Budget was not made or presented. Why? It has no overarching vision and goal. It has no strategy to boost demand and growth. It has no strategy for creating jobs. It did not understand the acute distress in rural India. It does not understand the angst and anger of the young people. Above all, by cutting expenditure -- I mentioned it earlier -- as a proportion to GDP, you have shown that your Government and your party has no empathy for the poor people. The most important thing in public life is a sense of equity and a sense of empathy. I can live without electricity. But, I cannot live without empathy, especially the poor people who lived without electricity since civilization began in village which has not electrified. But, he wants empathy. The Government must lean in towards the poor. The Government must say, 'We understand your problems. We

are here to help. We will help you as much as possible.' This Budget shows no empathy for the poor. And, after all this exercise, after contracting expenditure as a percentage of GDP, after devising no strategy for industrial revival or farm revival or job revival, after making a terrible mistake through demonetization, what have we achieved? In terms of fiscal goals, you say 3.2 per cent. After contracting expenditure, you cannot achieve your goal of 3 per cent which the hon. Finance Minister said last year. In the last year's Budget he said, 'Next year I will achieve 3 per cent.' In four Budgets in three years, you have chosen escape clause twice! You chose escape clause for the first time in 2015-16. The target should have been 3.6 per cent. You set it at 3.9 per cent. And, now, what does the CAG say -- not CGA, it is CAG; CGA is the Controller of Government Accounts -- and I relied upon the CAG's accounts? I am quoting to you the CAG, who is your most trusted and wanted Constitutional office-holder. Sir, 4.31 per cent is the fiscal deficit for 2015-16. You slipped badly in 2015-16. You are going to slip again in 2017-18. This 3.2 per cent carries no credibility at all. You have said 3.2 per cent, it should have been 3 per cent. Sir, 3.2 per cent carries no credibility at all. Even if you achieve 3.2 per cent after contracting expenditure, it is an admission of failure. You are neither on the path of fiscal prudence nor are you on the path of wise Budget management.

This Budget is a demonstrable failure of economic management. It will not take the country forward. It will not lift people out of poverty. It will not bring any relief to any section of the people. And, believe me, the powder keg that I spoke about, the young people who are waiting for jobs, waiting for job opportunities to open up are the ones most deeply disappointed, most deeply offended by this listless, directionless Budget.

I sincerely hope that corrective measures can still be taken before we meet again next to discuss the Finance Bill. Thank you.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Prabhat Jha.

(FOLLOWED BY USY/1W)

VNK-USY/1W/3.05

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, Shri Prabhat Jha.

श्री दिग्विजय सिंह : अब ये economist बोलने वाले हैं। ...(व्यवधान)...

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : नहीं, माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपके economist ने जो बजट प्रस्तुत किया था, उसको देश ने समझ लिया और 44 पर लाकर आपको खड़ा कर दिया। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री जितनी बार बजट प्रस्तुत करेंगे, 2019 का दरवाजा हमारे लिए वैसा ही खुला रहेगा, जैसा 2014 में खुला था। ...(व्यवधान)... दिग्विजय सिंह जी, आप जरा बैठ कर सुन लेते।

महोदय, 1 फरवरी, 2017, बसंत पंचमी का दिन था, जिस दिन बजट प्रस्तुत किया गया। कहा जाता है कि वह 'विद्या दायिनी, हंस वाहिनी' का दिन होता है ।

"धूप-छांव के बहते इस धरा को सजाने,

ऋतुराज को मनाने बसंत आ गया।

गीत प्रेम के सुनाने, मनमीत को मनाने,

सुख समृद्धि को बढ़ाने बसंत आ गया।।"

बसंत पंचमी के दिन प्रस्तुत यह बजट भारत के आर्थिक परिवर्तन का संकेत लेकर आया था और मैं समझता था कि इस संकेत को विपक्ष के लोग भी समझेंगे। मैं सदन में उस दिन का इंतजार करता रहता हूँ कि सत्ता पक्ष के द्वारा कोई तो अच्छी बात होगी, जिसकी प्रशंसा विपक्ष के लोग करेंगे, लेकिन वर्षों वित्त मंत्री रहे चिदम्बरम जी ने जिस तरह से कहा है कि यह होपलेस बजट है, विमुद्रीकरण का परिणाम क्या होगा, तो आपसे इसी तरह की भाषा की आशा थी, क्योंकि आप कभी भी आंख वाले को आंख वाला नहीं कह सकते, सूरदास को सूरदास नहीं कह सकते, आप सूर्योदय को अंधेरा कहने में विश्वास रखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2017-18 का जो बजट है, वह गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, दलितों के लिए है, शोषितों के लिए है, पीड़ितों के लिए है और यही बात है कि यह बजट आप जैसे समृद्ध लोगों की समझ में नहीं आ रहा है।

यह वर्ष पंडित दीन दयाल उपाध्याय, जो हमारे दर्शन के प्रमुख थे, उनके शताब्दी समारोह का वर्ष है और हमने यह वर्ष 'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यही कारण है कि इस बजट में भारत के गरीब को केन्द्र बिन्दु बनाया

गया है। पिछले बजट में भी सबसे पहले ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने, किसानों को.... हम हमेशा कहते रहे हैं, आज़ादी के पहले वर्ष में लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। कहते तो आप रहे, लेकिन इस देश में किसानों के लिए, गांवों के लिए बजट किसी ने प्रस्तुत किया है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी और अरुण जेटली जी के बजट ने प्रस्तुत किया है। आपके बजट में कभी किसान नहीं दिखे, आपके बजट में कभी गांव नहीं दिखा, आपके बजट में कभी गांव की समृद्धि नहीं दिखी। आपके बजट में आपने गांव, गरीब, मजदूर को सदैव दूर रखा है। ऐसा इसलिए था, क्योंकि उसका कारण था। आज़ादी के बाद आपने सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत किये। आपने 60 से अधिक बजट प्रस्तुत किये। मैं आज एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपने हमेशा वोटरों के लिए बजट प्रस्तुत किये, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नागरिकों के लिए बजट प्रस्तुत किया है। हमने लुभावने नारे नहीं दिए। हमने जो किया है और जो करते हैं, वही कहा है।

(उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) पीठासीन हुए)

आप वित्त मंत्रालय के indiabudget.nic.in पर चले जाइए। पिछली बार बजट में जितनी घोषणाएं की गई थीं, यह किसी से छुपा नहीं है, प्रत्येक विभाग व मंत्रालय ने 90 से 95 फीसदी अपना काम किया है, जो भी हमने बजट में कहा था। मेरी चुनौती है कि कोई साबित कर दे कि काम नहीं हुआ है। मैं आपके बजट का एक-एक उदाहरण दे सकता हूँ, जिसमें आपने दस साल पहले जो घोषणा की थी, वह आज भी पूरी नहीं हुई है। वह आपके 10 साल के कार्यकाल में नहीं पूरी हुई। आप क्या सुनना चाहते हैं? आप देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं, देश की जनता जानती है। 70 साल में

यदि लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात हुई है, तो देश की जनता मजबूत हुई है, उसकी जानकारी बढ़ी है। किसी अच्छी चीज को अच्छा कहने का साहस चाहिए और यह आज राजनीति की महती आवश्यकता है। इसलिए चिदम्बरम जी जैसे इतने विद्वान व्यक्ति, जो वित्त मंत्री रहे हैं, वे कह रहे हैं कि इसमें एक लाइन, एक शब्द काम का नहीं है। काम का कौन है, यह समय तय करेगा। मैं तो आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि इस देश में इस बजट में क्या-क्या किया गया है।

इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने 2017-18 के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए कई बड़ी बातें कही हैं और उनको करने की कोशिश की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी सहायता देते हुए सरकार ने ग्रामीण आवंटन को बढ़ा कर 1,87,233 करोड़ रुपए कर दिया है, जब कि 2016-17 के बजट में केन्द्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 87,765 करोड़ रुपए आवंटन किया था और आप कहते हैं कि कुछ किया ही नहीं, रक्षा में कुछ नहीं किया।

(1एक्स/एनकेआर-पीके पर जारी)

NKR-PK/1X/3.10

श्री प्रभात झा (क्रमागत) : यह किसने किया? क्या आपने कभी इसे बढ़ाया था, मुझे नहीं लगता। लेकिन हमने इस बार गांव की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राशि आवंटित की, जिसे आप देख सकते हैं। आपने बार-बार कहा, एक चैनल पर मैंने सुना कि मनरेगा में आपने कुछ नहीं किया। मनरेगा में सैटेलाइट से काम हो रहा है। पांच लाख से अधिक तालाब, आप साइट पर चले जाइए, भारत में यदि किसी ने बनाए हैं तो

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। आपने तो मनरेगा में गड्ढे खोद दिए थे, दूसरा कोई काम ही नहीं किया, लेकिन आज हम ऐसा दावे के साथ कह सकते हैं।

किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने की व्यवस्था की है। आपने क्या किया, क्या आप बता सकते हैं? किसानों को मजबूत बनाने की जरूरत है। खाली यह कहने से किसान मजबूत नहीं होगा कि भारत कृषि-प्रधान देश है, हमारा अर्थ उस पर आधारित है। ऐसा कहकर आपने वर्षों देश को छला है और छले हुए लोग अब जान गए हैं कि आप कैसी बातें करते हैं। जहां किसानों को बड़ी राहत देते हुए, इस सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, वहीं वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को कर्ज में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। क्या कभी आपने सोचा था कि पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात की जाए। लगातार इस सरकार की निगाह सैवन सिस्टर स्टेट्स पर है। लगातार हमारी निगाह जम्मू-कश्मीर स्टेट पर है। हमने उसे भारत का अविभाज्य अंग माना है और जब कहते हैं तो करते हैं।

इस साल खेती 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। माइक्रो-सिंचाई फंड के अंतर्गत आरंभ में 5 हजार करोड़ रुपए इस सरकार ने अपने बजट में रखे हैं। इतना ही नहीं, डेयरी उद्योग के लिए, नाबार्ड के जरिए 8000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। दुग्ध पैदावार के लिए 300 करोड़ रुपए से शुरुआत की गई है। हरदम मजाक नहीं होता है। यह किसानों के प्रति हमारी चिन्ता दर्शाता है, पशु-पालन के प्रति चिन्ता दर्शाता है। गांवों से जानवर भाग रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनकी रक्षा हो, उसकी चिन्ता की गई है। नाबार्ड में computerization को बढ़ावा दिया गया है ताकि किसानों को कर्ज

देने में उसे आसानी हो। इतना ही नहीं, अभी उर्वरक सबसिडी के बारे में माननीय चिदम्बरम जी कह रहे थे। वर्ष 2017-18 में उर्वरक क्षेत्र के लिए दी गई सबसिडी 70 हजार करोड़ रुपए होगी और जो स्तर 2016-17 में था, वही स्तर इस साल भी रहेगा। फास्फोटिक और पोटेशियम खंड के लिए सबसिडी को 6 प्रतिशत बढ़ाया गया है। भारत में संबंधित परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस आवंटन के साथ, डेढ़ लाख पंचायतों तक तीव्र गति से इंटरनैट पहुंचाने का काम करने का लक्ष्य रखकर इस क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की बात की जा रही है। कल एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम क्या कार्ड खाएंगे? देश का विकास और देश की प्रगति सिर्फ रोटी से नहीं होती है। हम लोगों के मन को जीतने का काम करते हैं। हम प्रगति के दौर में पीछे रहना नहीं चाहते। हम पुरातन को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन नूतनता की ओर बढ़ते हुए पुरातन के साथ भी काम करना चाहते हैं, यह हमारी कार्य करने की पद्धति है।

ग्रामीण इलाकों में 60 फीसदी सैनिटेशन का काम शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कृषि बाजार में 250 से बढ़ाकर 500 ए.पी.एम.सी. बनाने एक और स्वागत-योग्य कदम इस बजट में आया है। यह किसानों द्वारा अपने उत्पाद को बेचने के लिए अधिक विकल्प और नए रास्ते खोलने का काम करेगा। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 4,818 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, ताकि मार्च, 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा सके। आप दावे के साथ कहते हैं कि हमने यह प्रगति की, हम चन्द्रायन पर गए, हम मंगलायन पर गए, लेकिन आप गांवों में तो बिजली पहुंचा नहीं पाए। हमारे 18000 गांव

बिजली से वंचित थे। एक साल में पूरी तरह से उन गांवों को बिजलीयुक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है और उसके लिए बजट में 4818 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

(DS/1Y पर जारी)

DS-PB/3.15/1Y

श्री प्रभात झा (क्रमागत) : "प्रधान मंत्री आवास योजना" में ग्रामीणों हेतु आवास के लिए वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में किए गए 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि बेघर लोगों के लिए तथा कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए वर्ष 2019 तक एक करोड़ मकानों का निर्माण पूरा करा दिया जाए। यह इस सरकार की हिम्मत है कि यह सरकार निर्णय लेती है, फैसला लेती है और जो कहती है, उसको करने में विश्वास रखती है।

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" के लिए वर्ष 2017-18 के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में सड़कों का विस्तार किया जा सकेगा और गाँवों की सारी बारहमासी सड़कों को जोड़ने का भी काम किया जाएगा। इस पहल में सरकार की अहम भूमिका होगी। जब तक परिवहन नहीं होगा, तब तक गाँव का माल बाजार तक कैसे आएगा, गाँव का माल शहरों तक कैसे जाएगा? इसलिए इसके लिए 23,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में 133 किलोमीटर सड़क का प्रति दिन निर्माण किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 में यह 73 किलोमीटर था, यानी लगातार प्रगति हो रही है। मामला चाहे सड़क का हो, बिजली का हो या खेती का हो, इन सब मामलों में हमने बढ़ने की कोशिश की है।

पिछली बार "मनरेगा" के बारे में कहा गया कि आपने पैसे काट दिए। इस बार पैसे नहीं कटे हैं, बल्कि इस बार 48,000 करोड़ रुपये "मनरेगा" में देने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि "महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार योजना" के अंतर्गत 48,000 करोड़ रुपये दिए हैं। मोदी सरकार ने पिछले बजट में "मनरेगा" के लिए 38,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इस बार "मनरेगा" में 5 लाख तालाब खुदे हैं, अबकी बार यह तय किया गया है कि "मनरेगा" में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद से पूरा काम स्पेस टेक्नोलॉजी से लिया जाएगा और 10 लाख तालाब खोदे जाएँगे। "मनरेगा" में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। वर्ष 2014 के पहले "मनरेगा" में 25 से 30 फीसदी महिलाएँ काम करती थीं, जबकि आज इसमें 55 फीसदी महिलाएँ काम कर रही हैं। यह किसकी सफलता है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में वर्ष 2014 में 82 फीसदी सुधार हुआ, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 65 फीसदी गाँवों में स्वच्छता अभियान धड़ल्ले से चल रहा है। लोग जागरूक हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं कि नहीं, यदि मेरा गाँव स्वच्छ रहेगा, तो मेरा भारत स्वच्छ रहेगा। क्या यह काम नहीं करना चाहिए? इन बातों की प्रशंसा कौन करेगा? हमें आपकी प्रशंसा नहीं चाहिए, देश की जनता हमारी प्रशंसा कर रही है। यदि कुछ नेता चुप रहें, तो उससे हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने और वहाँ के लोगों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए "दीन दयाल अंत्योदय योजना" और "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" के आवंटनों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके ज़रिये एक करोड़ परिवारों को इस बार गरीबी-रेखा से बाहर किया जाएगा। हम कोई नारा नहीं लगाते। सन् 1971 से नारा लग रहा है- "गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ।" आपको हटा

दिया, लेकिन आप गरीबी नहीं हटा पाए। लेकिन, हमने कहा है कि अगर एक करोड़ लोगों को आवास देंगे, तो इसी सदन में अगले वर्ष हम आपके सामने कहते हुए मिलेंगे कि हमने एक करोड़ लोगों को आवास दिया, हम यह कहते हुए मिलेंगे कि हमने एक करोड़ लोगों को गरीबी-रेखा से ऊपर किया, क्योंकि हमारी नीयत में खोट नहीं है। हम नागरिकों को वोटर की निगाह से नहीं देखते कि कौन हमको वोट देगा? भारत बचेगा, देश बचेगा, तो हम बचेंगे। हम इस मानसिकता के लोग हैं और इसीलिए काम कर रहे हैं।

"प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" के तहत "क्रेडिट सहायता योजना" के लिए आवंटन को बढ़ा दिया गया है और इसको तीन गुना कर दिया गया है। आप रोज़गार के बारे में कह रहे थे। क्या रोज़गार सिर्फ नौकरी का नाम है? हम तो ऐसे लोग खड़े कर रहे हैं, जो केवल खुद नहीं कमा रहे हैं, बल्कि वे दूसरे लोगों को रोज़गार देने की चेष्टा की दिशा में बढ़ रहे हैं। वे खुद 10-50 लोगों को रोज़गार दें, ऐसा काम हम कर रहे हैं और यह बेरोज़गारी समाप्ति की दिशा में बहुत बड़ा कदम बढ़ रहा है।

हमारे इस बजट में सस्ते आवास और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणा भी की गई है। वित्त मंत्री ने साल 2016-17 के वर्ष में घोषित सस्ती आवास योजना में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

(1जेड/एमसीएम पर जारी)

श्री प्रभात झा (क्रमागत) : वर्ष 2017-18 में 30 और 60 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र के बजाय अब 30 और 60 वर्गमीटर कारपेट क्षेत्र की गणना की जाएगी। इस योजना के तहत कार्य प्रारम्भ होने के बाद भवन निर्माण पूरा करने की अवधि में मौजूदा तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है। यह काम कौन करता है? सामान्य मध्यम श्रेणी परिवार के लिए किया गया है, सस्ते आवास की आधारभूत संरचना रखने की कोशिश की गई है। हमने कहा है कि इससे सस्ते आवास में जुड़ी परियोजनाओं को आधारभूत संरचना से सम्बद्ध करने के लिए दो लाख रुपए देने की बात की गई है। राष्ट्रीय आवासीय बैंक द्वारा वर्ष 2017-18 में 20 हजार करोड़ रुपए के व्यक्तिगत आवासीय ऋण का पुनगर्ठन किया गया है, व्यवस्था की गई है। विमुद्रीकरण से बैंकों में नकदी प्रवाह बढ़ा है, जिसके चलते बैंकों ने आवासीय ऋण समेत अन्य ऋणों की भी कुछ दरें पहले से कम कर दी हैं। यही नहीं, प्रधान मंत्री द्वारा आवासीय ऋण पर ब्याज में रियायत की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

उपसभापति महोदय, ये लोग विमुद्रीकरण पर बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। मुझे हैरानी है कि देश के सामान्य नागरिक जो बैंकों की लाइनों में लगे हुए थे, उनके पास कितने चैनल वाले गए थे और पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है? 100 में से 80 लोग जो ग्रेज्युएट नहीं थे, दसवीं पास नहीं थे, वे चैनल पर यह कहते सुने गए कि यह जो विमुद्रीकरण है, वह भारत के भविष्य को बदलने वाला निर्णय है। आज हमें लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन कल भारत का भविष्य सुधरेगा। उनके लिए, उन गरीब लोगों के लिए भारत उनका सपना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ हमारे नेताओं का सपना क्या है। पता नहीं क्या हो गया है। अच्छी बात

को कब कहेंगे अच्छा, राजनीति में स्वस्थ परम्परा होनी चाहिए। हो सकता है कि हम जब वहां बैठते थे तो आपकी बुराई की होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर हमने बुराई की तो आप भी अच्छी चीजों को बुरा ही बुरा कहो, यह समझ में नहीं आता है। समय बदल रहा है। आप अगर समय के साथ नहीं चलोगे तो आपको समय झटका देगा। 405 वाली संख्या वाले लोग 44 पर आते हैं। चिंता यह करिए कि जनता 44 पर क्यों लाई आपको? आपने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया था, इसलिए लाई, ऐसा नहीं है। देश के साथ नीयत में खोट थी आपके। आपने जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की। हम नरेन्द्र मोदी जी के बिहाफ पर कह रहे हैं कि नरेन्द्र मोदी की सरकार इस देश को मूर्ख नहीं बना रही। इस देश को सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। हम गरीब के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि विमुद्रीकरण के बाद देश में जितने चुनाव हुए, उस समय एक उपचुनाव शहडौल में होता है। वहां हम कितने मतों से जीतते हैं? चंडीगढ़ पढ़े-लिखे लोगों का शहर है, 22 जगह भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, 21 जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती है और कांग्रेस शून्य, ज़ीरो, पटा सन्नाटा, साफ। कांग्रेस का चंडीगढ़ का अध्यक्ष चुनाव हारता है। यह है विमुद्रीकरण का खेल, अगर इसको हम आंकड़ों में देखना चाहते हैं आज। आइए, कहां चलेंगे आप, गुजरात में? आप चलेंगे महाराष्ट्र में? सारे नगर निकायों के चुनावों में क्या स्थिति हुई है? विमुद्रीकरण की आड़ में राजनीति मत करिए। इतना बड़ा साहस कौन ले सकता है। वोट की चिंता किए बगैर नरेन्द्र मोदी जी ने भारत माता के वैभव को ऊपर ले जाने के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया। क्या पड़ी थी उनको? उन्होंने कहा कि मैं फक्कड़ हूं, मुझे क्या है, मैं झोला लेकर आया था, झोला लेकर चल दूंगा,

लेकिन भारत माता को फक्कड़ नहीं बनने दूंगा, भारत माता को मजबूत बनाने के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह समझने की कोशिश करनी चाहिए।

इतना ही नहीं है, ये लोग फसल बीमा का मजाक उड़ा रहे थे। आपकी फसल बीमा योजना क्या थी? किसान का बैंक में जो पैसा जमा होता था, उसी में से काट लेते थे। आज क्या स्थिति हुई है? आज स्थिति यह है कि खेत ही नहीं, अगर खलिहान में फसल कट कर आ गई है और बारिश की वजह से फसल खराब होती है तो यह सरकार फसल बीमा के तहत उस किसान को पैसा देगी। आप देखिए तो सही, कुछ विचार करिए। 15 साल से हम छत्तीसगढ़ में हैं, 15 साल से हम गुजरात में हैं, 15 साल से हम मध्य प्रदेश में शासन क्यों कर रहे हैं? हमने गरीबों के आंसू पोंछने वाली योजनाओं को इस धरती पर साकार किया है। हमने दीन दयाल जी के उस सपने को पूरा किया है जो अन्त्योदय है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के आंसू पोंछने का काम किया है। (2A/SC पर जारी)

SC-KSK/3.25/2A

श्री प्रभात झा (क्रमागत) : राजनीति नौटंकी से नहीं होती, मित्रो। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि राजनीति सेवा का नाम है और सेवा करने का बीड़ा नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने उठाया है। यही कारण है कि उनके बजट में सेवा दिखती है, उनके बजट में गरीबों की गरीबी दूर करने के चित्र दिखते हैं और शायद जो हमें दिखता है, जनता को दिखता है, वह हमारे कुछ नेताओं को नहीं दिखता है।

लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कितने बड़े फैसले किए गए हैं। यह फैसला सामान्य नहीं है। लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए पचास करोड़ रुपए तक के

turnover पर Corporate Tax 30 प्रतिशत से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है। इसके बारे में कहिए तो सही कि आपने निर्णय लिया। यह निर्णय विमुद्रीकरण के बाद लिया गया है, उसके पहले नहीं लिया गया है। अगर ब्याज दर में कमी की है कि आप 30 फीसदी ब्याज नहीं देंगे, 25 फीसदी देंगे तो क्या यह अच्छी बात नहीं है? क्या लघु उद्योग इस देश में नहीं बढ़ने चाहिए? क्या मंझौले उद्योग नहीं बढ़ने चाहिए? अगर ऐसा निर्णय किया है तो कहीं तो आप प्रशंसा कीजिए। इससे 6.67 लाख कम्पनियां, यानी 96 परसेंट को लाभ पहुंचेगा। अब यह लाभ कितने गरीब मज़दूरों को मिलेगा। चिदम्बरम जी 40 करोड़ लोगों की बात कर रहे थे। अब इन 40 करोड़ में से 20 करोड़ तो यहां काम करते हैं, उनके भविष्य का फैसला तो सरकार ने अपने बजट में किया है। 40 करोड़ लोगों के आंसू यदि आप पोंछ देते, तो 44 पर नहीं आते। हमने 40 करोड़ नहीं, 125 करोड़ लोगों की आबादी वाले भारत में हर नागरिक की चिंता की है - अगर कोई व्यवसायी है तो उसकी चिंता की है, अगर कोई वहां काम करता है तो उसकी चिंता की है, खेत की चिंता की, खेतिहर मज़दूर की चिंता की, किसान की चिंता की, महिलाओं की चिंता की, गांधी जी के सपनों को साकार किया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ी एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति ने कहा कि गांधी जी के सपनों को साकार करने वाला गांधी जी के बाद अगर कोई इस धरा पर पैदा हुआ है, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेन्द्र मोदी, जिसने स्वच्छता मिशन को साकार किया है, गांधी के सपनों को साकार किया है। क्यों नहीं किया आपने? कौन सा पैसा लग रहा था उसमें? हम स्वयं तो साफ रहना चाहते हैं, लेकिन मोहल्ले को गंदा रखना चाहते हैं। जनता सब समझती है कि नेता जी सुबह से शाम क्या करते हैं। अब बड़ी पैनी निगाह से लोग नेताओं को

देखते हैं, इसलिए नरेन्द्र मोदी जी के बजट में अरुण जेटली जी ने सबसे बड़ा साहस दिखाया है कि राजनैतिक शुचिता की बात की गयी है। राजनैतिक शुचिता के बारे में आप तो कहते रह गए, लेकिन कुछ किया नहीं। हमने कहा कि अब 20 हज़ार रुपए नहीं, अगर कोई नकद देगा तो 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, उसके बाद उसको cheque देना है। क्या यह साहस है आपमें? आप नहीं कर सकते थे। अगर आप करते तो जनता समझती। भारतीय राजनीति में आए दिन नेताओं पर आरोप लगते हैं, इस देश में नौकरशाह और नेता बहुत बदनाम हो गए हैं। उन बदनाम नेताओं को बदनामी से रोकने का काम इस बजट में किया गया है और मैं नरेन्द्र मोदी जी तथा अरुण जेटली जी को इसके लिए बधाई देता हूं, वे और साहसिक निर्णय लें, चुनाव आयोग मज़बूती से निर्णय ले। देश का नेता यदि बेदाग होगा तो भारत की जनता का उठता विश्वास थमेगा और नेताओं पर विश्वास यानी लोकतंत्र पर विश्वास होगा। आज लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, यह शर्म की बात है, यह दुख की बात है। बातें करने से कुछ नहीं होता, जीवन जीना पड़ता है। देश देखता है कि मेरा नेता कैसा जीवन दे रहा है। यह बजट एक-एक भारतीय के जीवन के साथ जुड़ा हुआ बजट है।

हमें यह कहा जाता है कि हम एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, हम मुस्लिम विरोधी हैं। आप मुझे बताइए, कहां से विरोधी हैं? जब मैं मुम्बई में रहता था तो मेरे बगल में पनामा कम्पनी के एक जीएम रहते थे, वे हमारे पड़ोसी थे, महबूबा उनकी बेटी थी। रक्षा बंधन के दिन जब वह रोती थी तो मेरी मां मुझे भेजती थी कि महबूबा से राखी बंधाकर आओ। हम कभी भी इन बातों में नहीं पड़ते। केवल बदनाम करके राज करने की जो कोशिश की गयी, वह अच्छी बात नहीं है। राज़ खुलता है, इस

देश के मुस्लिमों को भी समझ में आएगा कि इस देश को इस विचारधारा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम किसी भी भारतीय के विरोधी नहीं हैं। जो राष्ट्रविरोधी है, उसके सब लोग विरोधी होंगे, लेकिन राष्ट्रभक्तों का विरोध कोई नहीं कर सकता, चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम हो।

इस बजट को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री, माननीय अरुण जेटली जी ने कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ज़ोर दे रही है। पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ज़ोर देते हुए बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आवंटन में 35 फीसदी से अधिक वृद्धि करने की घोषणा की है।

(2बी-जीएस पर जारी)

GS-GSP/2B/3.30

श्री प्रभात झा (क्रमागत): अब उसके बाद भी आप हम पर आरोप लगाएं। इस बजट में 35 फीसदी जितनी भी हमारी योजनाओं में राशि है, उसका आवंटन बढ़ाया गया है, बजट 2017-18 में अनुसूचित जातियों के लिए 38,833 करोड़ रुपये का आवंटन था और अब वह बढ़ाकर 53,393 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह लगभग 35 फीसदी है। अब इसे कौन समझेगा? आप हमारे ऊपर आरोप लगाते जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री तपन कुमार सेन: दूसरे Head से एडजस्ट कर दिया है।...(व्यवधान)...

श्री प्रभात झा: जी, हमने Head से एडजस्ट किया होगा, यहां तो Head ही साफ कर दिया गया। ...(व्यवधान)...

श्री तपन कुमार सेन: हम आपको टोकना नहीं चाहते थे। ...(व्यवधान)...

श्री प्रभात झा : आप तो Head ही साफ करते रहे हैं। ...(व्यवधान)... अगर यह नहीं होता, तो फिर पश्चिमी बंगाल में क्या होता? जो आपका हुआ है ...(व्यवधान)...

श्री तपन कुमार सेन: आप छोड़िए। अपने हिसाब के बारे में बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री प्रभात झा: दुनिया के मजदूरो, एक हो, ...(व्यवधान)... वह पार्टी 1962 में दो भागों में बंट गई। ...(व्यवधान)...मार्क्सवादी 1962 में दो भागों में बंट गई, सीपी (एम), सीपी(आई) में...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): No interruptions, please.

श्री प्रभात झा: बजट 2017-18 में अनुसूचित जाति के बारे में मैंने आपको बताया। अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन बढ़ाकर 31,930 करोड़ रुपये कर दिया है और अल्पसंख्यकों के लिए आवंटन बढ़ाकर 4,195 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह क्या कम बड़ी बात है। मैं देश के मुस्लिमों से कहना चाहता हूं कि आप इस बजट को पढ़ो कि आपके लिए कितने स्कॉलरशिप्स बढ़ाए गए हैं। प्रधान मंत्री जी ने बताया है कि स्कॉलरशिप्स में 50 हजार करोड़ रुपये खा जाते थे। फर्जी राशन कार्ड में 13,000 करोड़ रुपया सरकार ने बचाया है। कहां-कहां पर कितने गड्ढे थे, 70 साल से यही काम हुआ है, उसमें से पांच साल, दस साल छोड़ दीजिए।

इस देश में बहुत बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों के लिए इस सरकार ने एक फैसला लिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की एक नई पेंशन योजना की घोषणा इस सरकार ने की है, उसमें उनके लिए 8 फीसदी ब्याज सुनिश्चित किया गया है। अगर बुजुर्ग ने लाठी पकड़ ली है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बेकार हो

गया है, उसको भी जीने का अधिकार है। उसके आशीर्वाद से उसका घर फलता-फूलता है और इसीलिए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की चिंता की है।

हमने बजट में किफायती घर की बात की है। किफायती घरों को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे बिल्डरों को सस्ते मकान बनाने में सरकारी मदद मिल पाएगी और निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा।

अब ब्लैक मनी की बात बहुत कही गई है। उसके बारे में अरुण जी ने भी कल कह दिया और मैं भी कह रहा हूं। वे लोग चिंतित क्यों हैं, ब्लैक मनी बाहर निकलनी चाहिए, यह सब चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ लोग चिंतित हैं। अब जो लोग चिंतित हैं या तो वे ब्लैक मनी वाले होंगे या उनके घर में होगा। ब्लैक मनी का सब विरोध करते हैं, लेकिन चिंता क्यों कर रहे हो? आपको सरकार के हाथ में हाथ मिलाकर कहना चाहिए था कि हम आपके साथ खड़े हैं, काश भारतीय राजनीति में ऐसा होता, तो ब्लैक मनी वालों के हौसले बुलंद नहीं होते, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने भरे सदन में कहा है कि तीन महीने से मुझ पर जुल्म हुआ है, चाहे जितना जुल्म हो, नरेन्द्र मोदी जनता के सामने झुकेगा, लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुकेगा। इसलिए काला धन जिन लोगों ने रखा है, उनको बरबादी के ठिकाने पर जाना ही पड़ेगा। काला धन अब इस देश का धन नहीं कहलाएगा। काला धन रखने वालों को जेल के सीखचों में रखने का काम यह सरकार करेगी। इतना ही नहीं किया है, तीन लाख से अधिक की निकासी बंद करके हमने बहुत बड़ा रिफॉर्म करने की कोशिश की है। इससे तीन लाख रुपये से अधिक की निकासी बंद होगी और उसके लिए अलग से सरचार्ज लगेगा।

डाक घरों में पांच लाख एम्पलाइज़ हैं, उनका क्या उपयोग हो, उसके लिए आपने क्या किया? हर डाक घर को बैंक बनाने की कोशिश और डाक घर से पासपोर्ट देने की कोशिश, सब डाक घरों को काम देने की बात को इतना minutely कौन सोचता है ? सरकार ने एक-एक व्यक्ति के बारे में सोचने का प्रयत्न किया है। आई.आर.सी.टी.सी. से रेल टिकट सस्ते होंगे। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं।

अब इतना ही नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। कोई पैसा लेकर भाग गया, तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेन्द्र मोदी की सरकार ने भगा दिया। पैसा आपने दिया, भगा हमने दिया। कितनी बड़ी बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वे कागज प्रस्तुत हुए हैं, बैंकों के पेपर्स बाहर आए हैं कि किसकी सरकार के कहने पर, किस सरकार के कहने पर संबंधित व्यक्तियों को पैसे दिए गए? अब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने, अरुण जेटली जी ने वित्त बजट में यह साफ कहा है कि भगोड़ों के दिन लद गए, अब भगोड़े बचेंगे नहीं, जो पैसा बैंक का, सरकार का लेगा, वह भाग नहीं सकता। (HMS/2C पर जारी)

HMS-SK/3.35/2C

श्री प्रभात झा (क्रमागत) : भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने के लिए ऐसा कानून लाया जाएगा, जिनके विदेश में होने के बावजूद भारत में उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। हम यह साहस इसलिए करते हैं क्योंकि इस सरकार की morality high है, जिस में नैतिकता है। ऐसे फैसले वही सरकार लेती है, जो नैतिक रूप से मजबूत होती है।

अब रही बात आधार कार्ड की अहमियत की। हमने कभी आपके "आधार" की बुराई नहीं की, लेकिन "आधार" को अहमियत देने के लिए, उसकी पूर्णता के लिए इस

में बात कही गयी है - वरिष्ठ नागरिकों के लिए "आधार" से जुड़े हैल्थ कार्ड बनेंगे, कारोबार आसान बनाने के लिए सरकार ने कंपनीज के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, पासपोर्ट के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, मैनेजर तथा "डीमैट" अकाउंट के लिए, पंजीकरण के लिए आधार कार्ड का उपयोग होगा। इस तरह आम लोगों को राहत देने की बात कही गयी है।

अब आयकर की बात करें। आपने कहा, कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आपने तो टैक्स पर टैक्स लगाया। यहां पहली बार वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सालाना 3 लाख रुपए तक की आय वालों को अब कोई कर नहीं देना होगा। यह इस सरकार ने फैसला किया है और इस के आगे 3 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत टैक्स के बजाय केवल 5 फीसदी कर लगेगा। यह इस सरकार का फैसला है। यह मध्यम श्रेणी के परिवारों के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, हमने तो बीड़ा उठाया है, आप अच्छा करोगे तो हम बुरा कहेंगे। कहिए, लेकिन देश की जनता अच्छे और बुरे का फर्क समझती है। उसे जानकारी रहती है। उपसभाध्यक्ष जी, 5 से 10 लाख की आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। ये सारी बातें इस बजट में कही गयी हैं। मैं ऐसी एक नहीं, अनेक बातें गिना सकता हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, ये कुछ मोटी-मोटी बातें हैं, जो मैं कहना चाहता हूं। आप देखिए कि इस देश में गरीबों के नाम पर उनका शोषण किसने किया और आज हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें अगर हम कहीं से कुछ निकालते भी हैं, तो हमारे सामने गरीब रहता है, उसकी हड्डियां और मांस-पेशियां दिखती हैं, उसकी चमड़ी

और रोटी के अभाव में चिपका पेट दिखता है। हमारी कोशिश रहती है कि गांव हरा-भरा रहे, गांव के किसान की फसल लहलहाती रहे, किसान के चेहरे पर मुस्कान आए और इसलिए इस सरकार ने अपने बजट में सब से बड़ी प्राथमिकता गांव को, गरीब को, और किसान को दी है। हम सिर्फ यह नहीं कहते कि भारत कृषि प्रधान देश है। अगर भारत कृषि प्रधान देश है, यदि उसका कृषि आधारित अर्थ-तंत्र है, तो किसान को मजबूत बनाना होगा। उपसभाध्यक्ष जी, चिदम्बरम साहब दोगुनी आय का मज़ाक उड़ा रहे थे। आप मध्य प्रदेश में आइए और देखिए कि शिवराज सिंह सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का निर्णय लिया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाकर दी है। मैं चिदम्बरम जी को निमंत्रण देता हूं, आप 7 दिनों के लिए मध्य प्रदेश आइए। हमारी योजनाओं को देखिए, हमारे किसानों से बात कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि यह सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के लोग अभी से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो चौथी बार आएगी।

उपसभाध्यक्ष जी, हम हमदर्दी से काम करते हैं, सच्चाई से काम करते हैं, हम दिल से काम करते हैं। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। पूर्व वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम आंकड़ों की जुगाली नहीं करते। आपने सिवाय आंकड़ों की जुगाली के क्या किया? आप अंत में विमुद्रीकरण पर रोए। आप क्यों इतने दुखी हो रहे हैं? आप कम-से-कम जनता को गुमराह मत कीजिए। उपसभाध्यक्ष जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस सदन में बहुत अच्छे लोग हैं। इसे "अपर हाउस" कहा जाता है। अब लोग कैसे आते हैं, यह मैं नहीं जानता? जब मेरे जैसे लोग आते हैं, तो सब लोग आ सकते हैं, लेकिन इस

की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा कि भारत की अर्थ-व्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है और उसके साथ एक पुंछल्ला जोड़ दिया कि नहीं, यूपीए की सरकार में भी तीव्र गति से बढ़ रही थी। आपकी गति तो तीव्र गति से बढ़ रही थी, लेकिन जनता में क्यों घट रही थी, यह आप हमें समझा दो। जनता तीव्र और मंद दोनों का अंतर समझती है। जब तक आपकी आंखों के सामने जनता नहीं होगी, आपका बजट साकार नहीं होगा। जनता इस बजट की आत्मा है, इस में भारत की आत्मा भारत का गरीब है, इसलिए इस बजट को हम सब ने स्वीकार किया है। हमने इसे आद्योपांत, पहले पृष्ठ से आखिरी पृष्ठ तक पढ़ने की कोशिश की है।

(2डी/एएससी पर जारी)

ASC- YSR /2D/3.40

श्री प्रभात झा (क्रमागत) : यह बजट किसी भी सरकार की "गीता" होता है और इसको अर्थ-गीता कहते हैं। इसके शब्द इसकी ऋचाएं होती हैं, इसलिए इसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। हम राजनीति में एक दूसरे के विरोधी होंगे, हमारे मत अलग-अलग होंगे, लेकिन इस तरह का मत नहीं होता है कि हम उसे एक सिरे से खारिज कर दें। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि पी. चिदम्बरम जी, आप प्लीज़ इस बजट को दोबारा पढ़िए। शायद आपको यह पहली बार पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया होगा। आप इसको तीन-चार बार पढ़ेंगे, तो शायद आपकी समझ में यह आ जाएगा। जब तक आप गरीब को नहीं समझोगे तब तक वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के इस बजट को नहीं समझ पाओगे। जिस दिन गरीब की पीड़ा को समझ लोगे, उसी दिन इस बजट को

समझ लोगे। मैंने यहां जो भी बातें रखने की कोशिश की है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, दलित, महिला, शिक्षा और रोजगार आदि सब चीजों को लेकर केन्द्रित करके बात की है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के इस शताब्दी समारोह में हमारे केन्द्र बिन्दु में जो गरीब है, उस गरीब को लेकर यह बजट आगे बढ़ेगा। अगर यह बजट ऐसा ही रहा, तो 2019 हमारी बाट जोह रहा है। कल गाजियाबाद की सभा में प्रधान मंत्री जी ने दावे के साथ कहा कि हम जब 2019 में आएंगे, 'घोषणापत्र' जिसे मैं संकल्पपत्र कहता हूं, उसके एक-एक शब्द के साथ आपके बीच में आएंगे। मैं फिर कहता हूं कि आप एक बार फिर जाकर देखिए। यह वह पार्टी है और इसकी यह सरकार है, जिसने पिछले बजट में जो कहा था, उसको 90-95% पूरा किया है और जो काम पूरा नहीं हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, इतना प्रतिशत पूरा है। जिस सरकार में इतनी पारदर्शिता हो और जो सरकार इतनी ईमानदारी से काम करे, उसे जनता कभी नहीं छलती है। जो काम नहीं करते हैं और जो जनता को छलते हैं.... मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

"अंधकार दे रहा चुनौती, दीप जलाने के दिन आए।
झोंपड़ियों में नई क्रांति का, अलख जगाने के दिन आए।
आज स्वयं को नहीं राष्ट्र को सबल बनाने के दिन आए।
कण-कण की रक्षा हित अगणित शीश चढ़ाने के दिन आए।
दीप जलाने के दिन आए, अंधकार दूर करने के दिन आए।
अंधकार हटेगा, दीप जलेगा, सवेरा होगा ।"

यदि मैं इसके आगे कहूंगा, तो आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का नारा है, इसलिए मैं वह नहीं कहूंगा, लेकिन यह सत्य है कि सवेरा होगा, गरीब मुस्कुराएगा, तो कमल खिलेगा।

(समाप्त)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय बजट 2017-18 पर साधारण चर्चा के दौरान बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी पार्टी के नेता को धन्यवाद देता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रोफेसर साहब को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2012 में जो घोषणापत्र जारी किया था, उसके तहत उत्तर प्रदेश में सारे वायदे पूरे करने का काम किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपने घोषणापत्र में जो कहा था, मैं समझता हूं कि उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। यह बजट निराश करने वाला और दिशाहीन बजट है। यह किसान, गांव और गरीब विरोधी बजट है। इसमें बजट भाषण के सिवाय कुछ नहीं। ये लोग चुनाव के लिए, युवाओं के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि हम सभी को रोजगार देंगे। तीन साल का समय हो गया है, लेकिन ये किसी एक भी आदमी को रोजगार नहीं दे पाए। इन्होंने दो करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन ये हजार लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। नोटबंदी के बाद करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं और लोगों ने आत्महत्याएं कीं, लाइन में खड़े सैकड़ों लोग मरे, उनके प्रति आज तक इन्होंने संवेदना तक व्यक्त नहीं की है, तो इससे खराब बात और क्या हो सकती है? इस बजट में किसानों और

युवाओं को नौकरी देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मान्यवर, अभी झा साहब बड़ी लम्बी-लम्बी बातें कर रहे थे। (2E/LP पर जारी)

LP-VKK/3.45/2e

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : वैसे चिदम्बरम साहब ने इनको आईना दिखाने का काम किया है और बताया है कि देखिए, आपने कहा क्या था और किया क्या है? आज देश में सभी नौजवान, किसान, गरीब परेशान हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी पूरे विश्व टूर पर जाते हैं, लेकिन अगर ये विदेशों से तुलना करते हैं, तो मैं बता दूं कि वहाँ रोजगार की गारंटी है। वहाँ जो भी बच्चा बैचलर हो जाता है, पढ़-लिख जाता है, उसके लिए रोजगार की गारंटी है। महोदय, हम जो हर वर्ष करोड़ों बेरोजगारों की फ़ौज तैयार कर रहे हैं, आपने उनके लिए क्या व्यवस्था की है? मैंने प्राइवेट मेम्बर बिल के माध्यम से इस विषय को रखा था कि जब केंद्र सरकार नोटबंदी कर सकती है, तब ऐसा कानून भी बनाए, जिससे पूरे देश के नौजवानों को, जो नौजवान अठारह साल से अधिक की उम्र का हो जाए, जिसको वोट देने का अधिकार है, उसको नौकरी पाने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन बजट में इसका कहीं अता-पता नहीं है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

महोदय, आज देश किधर जा रहा है? इनके नेता जिस तरह से भाषणबाजी करते हैं, उस वजह से तमाम दंगे फैल जाते हैं, अव्यवस्थाएँ फैल जाती हैं। गुजरात में तमाम लोगों की दुकानें लुटीं, मकान लुटे, हरियाणा में तमाम लोगों के घर लुटे, उनकी दुकानें लुटीं, लेकिन उनको आज तक दस रुपये की मदद भी नहीं दी गई। इन्होंने

बजट में आज जो कहा है, उसके लिए हम कहना चाहते हैं कि जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होगा, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक कोई लाभ नहीं होगा।

सर, आप बड़े-बड़े वायदे करते हैं, लेकिन देश में जो दोहरी शिक्षा प्रणाली है, आपने उसको खत्म करने के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं किया? गरीब का बच्चा आपके प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, जहाँ आपने मिड-डे मील लागू कर दिया है, जहाँ सड़ा-गला खाना है, वही चावल हैं, जिनको खाकर बच्चे बीमार हो जाते हैं। यह खाना खाने से कितने बच्चे बीमार हो गए, मर गए? मैं पूछता हूं कि उनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है? जब बच्चा स्कूल में आता है, तो अपना कटोरा और थाली लेकर आता है। जब खाना पकने लगता है, तो उसकी निगाह उधर जाती है, मास्टर की निगाह भी उधर रहती है कि कहीं बनाने वाला कोई चोरी न कर ले। बच्चों को खाना खिलाकर आपने इन प्राइमरी स्कूलों को केवल भोजनालय बना दिया है।

महोदय, गरीब का बच्चा आपके प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा और अमीर का बच्चा कॉन्चेन्ट स्कूल में पढ़ेगा। हमारी पार्टी की माँग है, माननीय मुलायम सिंह जी हमेशा कहते हैं कि दोहरी शिक्षा प्रणाली खत्म करनी चाहिए और सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आपके इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

मान्यवर, इन्होंने चिकित्सा के बारे में "टी.बी. मुक्त भारत" बनाने का जिक्र किया है, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने तीन साल में क्या किया है? आप 2025 की बात करते हैं, जबकि आपको 2019 तक रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में लोग कैंसर से परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मुम्बई में जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है,

आपको उसकी तर्ज पर हर स्टेट में एक-एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आज बड़ा आदमी तो चालीस से पचास लाख रुपये खर्च करके विदेश में इलाज करा लेता है, लेकिन गरीब आदमी क्या करे? आज कैंसर की बीमारी पूरे देश में भयानक रूप में पैदा हो गई है, लेकिन इसके लिए केंद्रीय बजट में कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है।

मान्यवर, इन्होंने कृषि के बारे में बताया है। इन्होंने फसल बीमा, सिंचाई, हैल्थ कार्ड के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने की बात कही है। मान्यवर, हम किसान के बेटे हैं। इनका बैंक मैनेजर बिना रिश्वत के क्रेडिट कार्ड नहीं बनाता है। यदि रिन्युअल कराना होता है, उसकी लिमिट बढ़ानी होती है, तो उनसे 10 परसेंट या 15 परसेंट कमीशन लेकर रिन्युअल करने का काम करता है। जिस तरह पूरे देश में नोटबंदी के दौरान केंद्र सरकार में बैठे हुए बैंक के अधिकारियों ने काला बाज़ारियों के कारण बड़े लोगों के, अमीर लोगों के नोट बदलकर उनके घर पहुंचाने का काम किया है, वह अनुचित है। गरीब आदमी दो महीने लगातार मरता रहा, इसके कारण सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन आज भी लोगों के घर में खाने के लिए उनका अपना पैसा नहीं है।

महोदय, बेटी की शादी करनी थी, लेकिन इस कारण से लोग उनकी शादी नहीं करवा पाए। इस कारण से जिनके रिश्ते टूट गए, क्या आप उनके रिश्ते वापस जुड़वा देंगे? नोटबंदी के दौरान जो लोग मर गए, क्या आप उनकी जान वापस कर देंगे? आप यह नहीं कर सकते हैं।

(klg/2f पर जारी)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत): यह सारा दोष आप पर जाएगा। आपको पता चलेगा, अभी जो यह चुनाव हो रहे हैं और आगे 2019 में होंगे। जनता तैयार खड़ी है, नोट की चोट वोट के माध्यम से देने का काम जनता करेगी, तब आपको पता चलेगा।

आप एफडीआई की बात करते हैं, पहले तो आप एफडीआई का विरोध करते थे, जब आप विपक्ष में थे। आपको याद होगा, एक ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आ गई और सैकड़ों साल तक अंग्रेज देश पर काबिज़ हो गए। उनको हटाने में महात्मा गांधी से लेकर हमारे कितने महापुरूषों ने अपना योगदान दिया और चन्द्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे कितने ही लोगों ने अपनी जान की कुरबानी दी। आप कैसी विदेश नीति अपना रहे हैं? हमारे यहां विदेशी कंपनियों को ला रहे हैं। उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वे कब पैसे लेकर उड़ जाएंगे। इसके लिए आप चिंतित नहीं हैं। आपको अमीरों की चिंता है। आप बजट में कह रहे हैं कि एनसीआर में मकान सस्ते हों। आप पता लगा लीजिए, कितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, कितने मकान बनाने वाले लोग हैं? जब आपने नोटबंदी कर दी, तो उनके बने मकान आज कोई ले ही नहीं रहा। वे लोग गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, कहीं चले जाइए, सब्जी की तरह पर्चा लेकर रोड पर खड़े होकर घूम रहे हैं कि आप यह ले लीजिए, आपको किश्तों में दे देंगे। आपसे सस्ता तो वे बिल्डर्स लोग दे रहे हैं, जो मकान बना कर पछता रहे हैं। आपके बजट में तो आपने गरीब से लेकर सभी लोगों को बरबाद करने का काम किया है। अगर आपको देखना है, तो आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए। आज दूसरे प्रदेशों के लोग उसकी नकल कर रहे हैं। वहां के माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, बच्चों को नेट से जोड़ने के लिए, चूंकि आज जो फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे रेल का टिकट बनाना हो या

परीक्षा फॉर्म भरना हो या दूसरी ऐसी कोई व्यवस्था करनी हो तो बिना नेट के काम नहीं चलता, उन्होंने बीस लाख से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया है और 55 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को "समाजवादी पेंशन" देने का काम किया है, जो वृद्ध हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं थे। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी थी, पूरे देश में गरीब लोगों का सर्वे कराना चाहिए था कि देश में कितने लोग गरीब हैं? आज तक आपको यह पता नहीं है कि देश में कितने गरीब लोग हैं, जिनका बीपीएल कार्ड बनना चाहिए। जो बने भी, तो बीपीएल का नाम एपीएल में और एपीएल का नाम बीपीएल में, आपने यह काम किया है। "लोहिया आवास योजना", उत्तर प्रदेश में है, उससे सीखिए। आप 70 हजार, एक लाख रुपए का मकान दे रहे हैं। बड़े आदमी का तो फाइव स्टार होटल में रुकने का एक दिन का किराया एक लाख रुपए होता है और गरीब को एक लाख में मकान दे रहे हैं। महंगाई आसमान पर चली गई है। आपकी नोटबंदी और तमाम ऐसी नीतियों के कारण बालू के दाम, मैंने कल मामला उठाया था, मध्य प्रदेश में जिस तरह से बालू खनन हो रहा है, एक लाख रुपए में एक ट्रक बालू मिल रहा है और वह भी चोरी से बालू उठाया जा रहा है। अगर कोई व्यापारी तीन लाख रुपए लेकर कहीं जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का उड़नदस्ता घूम रहा है, इन्कम टैक्स वाले घूम रहे हैं और वहां एक-एक ट्रक से दस-दस हजार रुपए वसूले जा रहे हैं, एक-एक दिन में एक-एक करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। आपको यह पता नहीं है, वे चूंकि जानते हैं कि सब हमारे आदमी हैं, हमारी सरकार है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, वहां 108 नंबर, 102 नंबर "समाजवादी एंबुलेंस व्यवस्था" माननीय अखिलेश यादव जी ने चालू की, जिससे ऐसी महिलाएं जो प्रसव-पीड़ा से

पीड़ित थीं या एक्सीडेंट से पीड़ित लोग थे, उन लाखों लोगों की जान बचाने का काम किया है।...(व्यवधान)... इसी तरह 100 नंबर, हर दस किलो मीटर पर उत्तर प्रदेश में एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है। चले जाइए, वहां इतनी शानदार पुलिस की व्यवस्था हो गई है। ....(व्यवधान)... दिल्ली में क्या स्थिति है? ...(व्यवधान)...

श्री मेघराज जैन: उत्तर प्रदेश पर बोल रहे हैं या आप बजट पर बोल रहे हैं?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: जब आपका नंबर आए, आप बोल लेना।

श्री तपन कुमार सेन: अभी आपके वक्ता तो मध्य प्रदेश का बता कर गये है। थोड़ा हजम कर लो। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): प्लीज़, आपस में मत बोलिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में जो प्रावधान किया और जो केन्द्र सरकार से पुलों के लिए सड़कों के लिए पैसा मांगा, तो केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया, कोई पैसा नहीं दिया। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आगरा-लखनऊ जैसा हाईवे, नेशनल हाईवे बनवा कर तैयार किया, जिस पर लड़ाकू विमान उतारा गया, जिसे पूरी दुनिया के लोगों ने देखने का काम किया है।

(2जी/एकेजी-आरएल पर जारी)

AKG-RL/2G/3.55

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : मान्यवर, इनका बजट पूरी तरह से दिशाहीन है। हम किसान लोग हैं। हम चाहते थे कि मनरेगा में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे खेत का पानी खेत में होना चाहिए। हम चाहते थे कि मनरेगा में जिसका खेत है,

उसी को काम मिले। वह अपने खेत में तालाब बना ले और उस तालाब में थोड़ा सा पक्का pond बना ले, क्योंकि पानी जल्दी खत्म हो जाता है और फिर आखिरी फसल के लिए उसके पास पानी नहीं रह जाता है। लेकिन इनके बजट में किसान के खेत की सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इनका बजट बिल्कुल दिशाहीन है।

मान्यवर, छात्रों के लिए शिक्षा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए इस बजट में कहीं ऋण की व्यवस्था नहीं है। आज छात्रों की जो फौज है, वह परेशान है। आपको उनके लिए बिना ब्याज के ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके ऊपर कर्ज का ब्याज इतना अधिक हो जाता है कि अगर उस बेचारे को नौकरी नहीं मिली, तो या तो वह फाँसी लगा लेता है या घर छोड़ कर भाग जाता है या उसका मकान कुर्क कर लिया जाता है। यह छात्रों की हालत हो गई है। आपके बजट में छात्रों के लिए ऋण की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे देश के छात्र निराश हैं। आपका यह बजट बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला है।

मान्यवर, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड में हर तीन साल में सूखा पड़ता है। कोई ऐसा समय नहीं है, जब वहाँ सूखा न पड़ा हो। वहाँ पूरा का पूरा किसान भुखमरी के कगार पर आ गया है और वह पलायन कर रहा है। वहाँ पर न तो सिंचाई की व्यवस्था है और न पीने के पानी की व्यवस्था है। सूखा, ओलावृष्टि और बाढ़ से किसान बर्बाद हो जाता है।

मान्यवर, मैं अन्ना प्रथा के सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लाखों गायें किसानों की फसल उजाड़ रही हैं। आप गौ माता कहते हैं। आप उन गौ माताओं को लेकर उनके लिए पशु आश्रय केन्द्र खुलवा दीजिए

या गौशाला खुलवा दीजिए और उनके लिए चारा-पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। आप गौ माता की दुहाई देते हैं, लेकिन आपके बजट में अन्ना प्रथा को बंद करने के लिए एक रुपए की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे बुंदेलखंड का किसान ऐसी ठंडक में, जाड़े में अपने खेत में पड़ा रहता है। वह परेशान है। अगर उसको नींद लग गई, पूस की ठंड के ऊपर प्रेमचंद जी की कहानी है, अगर उसको दो बजे रात में ठंड की वजह से नींद लग गई, तो उसका पूरा का पूरा खेत जानवर चर जाते हैं, जिससे किसान बर्बाद हो गया है।

मान्यवर, इन्होंने 2022 तक सभी को मकान देने के बारे में कहा है। इसके लिए इन्होंने 30 मीटर से 60 मीटर के मकान बनाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था के बारे में कहा है। इन्होंने 4 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था के बारे में कहा है, जो ऊँट के मुँह में जीरा है। मान्यवर, मैं इनसे पूछँगा कि आपने 2014 से लेकर 2017 तक कितने लोगों को रोजगार दिया है?

मान्यवर, मैं रक्षा के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहूँगा। हमारे देश की सीमाएँ सिकुड़ रही हैं। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने सियाचिन की पहाड़ियों में, कारगिल में जाकर वहाँ की स्थिति देखने का काम किया और वहाँ फौजियों की जो परेशानी थी, उन परेशानियों को दूर करने का काम किया। अगर उस समय कोई फौजी शहीद होता था, तो उसकी टोपी और एक महीने की तनख्वाह आया करती थी। हम मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहेंगे कि जिस समय वे रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि जो फौजी शहीद होता है, उसकी

मिट्टी, उसकी अर्थी हवाई जहाज से उसके घर पहुँचाई जाए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसके लिए 20 लाख रुपए की मदद की व्यवस्था की, जिससे उसकी पत्नी, उसके आश्रित की मदद होती है। आज 30 किलोमीटर से ज्यादा चीन की तरफ से हमारी सीमाएँ सिकुड़ रही हैं।

मान्यवर, आज हम अपने देश में रोजगार की चिन्ता करते हैं। हमारे देश में जिस तरह से चीन का व्यापार बढ़ा है, उससे हमारे देश के सारे के सारे कुटीर उद्योग-धंधे चौपट हो गए हैं। हमारे देश में चीनी उत्पाद बढ़ा है और हमारा घरेलू उत्पाद घटा है। सारी मिल्स, चाहे पेपर मिल्स हों, चाहे कपड़ा मिल्स हों, सारी की सारी मिल्स बंद हो रही हैं। खिलौने और छोटी-मोटी चीजों से लेकर कई चीजों से पूरे देश का बाजार चीनी सामानों से पटा है।

(2एच/एससीएच पर जारी)